



2026:AHC: 179997

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 3389 वर्ष 2025

संजय सिंह उर्फ शनी

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता

: विजय शांतम

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, त्रिपुरारी पाल

न्यायालय संख्या- 92

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा थाना हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में भा.द.सं. की धाराओं 147, 148, 149, 301 और 307 के अंतर्गत सत्र विचारण संख्या 589 वर्ष 2017 (राज्य बनाम राघवेंद्र और अन्य) में पारित आदेश दिनांक 02.06.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा, अभियुक्त-पुनरीक्षणवादी राघवेंद्र उर्फ कल्लू की ओर से प्रस्तुत एक आवेदन पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त अभियुक्त को पी.डब्ल्यू.-1, संजय सिंह उर्फ शनी, और पी.डब्ल्यू.-2, सुमित कुमार से जिरह करने का अवसर प्रदान किया गया।

अभिलेख इंगित करता है कि अभियुक्त राघवेंद्र उर्फ कल्लू की ओर से उनके अधिवक्ता के माध्यम से द.प्र.सं. की धारा 311 के अंतर्गत एक आवेदन, प्रपत्र संख्या 53-ख प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें पी.डब्ल्यू.-1, संजय सिंह उर्फ शनी, और पी.डब्ल्यू.-2, सुमित कुमार से जिरह करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था, और यह तथ्य अभियुक्त के संज्ञान में केवल तब आया जब अंतिम तर्कों की तैयारी फिर से शुरू की गई। यह कहा गया था कि जिरह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



करने का अवसर समाप्त नहीं किया गया था और, तदनुसार, पूर्वोक्त साक्षियों से जिरह करने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदन का विरोध किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि मामला पहले ही अंतिम सुनवाई के प्रक्रम पर पहुंच चुका था और द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान में, अभियुक्त ने यह नहीं कहा था कि उसे पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 से जिरह करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। ऐसे आधार पर, आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की गई थी।

हालांकि, विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर, आवेदन को स्वीकार कर लिया और पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 से जिरह करने का अवसर प्रदान किया, यह ध्यान देते हुए कि वास्तव में अभियुक्त, अर्थात् राघवेंद्र उर्फ कल्लू द्वारा उक्त साक्षियों से जिरह नहीं की गई थी, और जिरह करने के उसके अवसर को न्यायालय के किसी आदेश द्वारा स्पष्ट रूप से समाप्त नहीं किया गया था।

पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 दोनों का पहले ही परीक्षण किया जा चुका था और अन्य सह-अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उनसे जिरह की गई थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि ऐसी जिरह के समय पुनरीक्षणवादी उपस्थित था और, कार्यवाहियों का ज्ञान होने के बावजूद, उसने अपनी जिरह नहीं की। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि साक्ष्य पूरा होने के पश्चात और अंतिम तर्कों के स्तर पर, किसी भी उचित आधार के अभाव में पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 से आगे जिरह करने की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं था।

हालांकि, सुनवाई के दौरान, पुनरीक्षणवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां काफी आगे बढ़ चुकी हैं और बाद के घटनाक्रमों के दृष्टिगत, वह वर्तमान पुनरीक्षण पर बल नहीं देना चाहते हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि पुनरीक्षण निष्फल हो गया है और तदनुसार इसे खारिज किया जा सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इस न्यायालय ने प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

आक्षेपित आदेश में यह विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज है कि अभियुक्त राघवेंद्र उर्फ कल्लू की ओर से पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 से जिरह नहीं की गई थी और उसके जिरह करने के अवसर को स्पष्ट रूप से समाप्त नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने, अभियुक्त को अपना बचाव करने का निष्पक्ष अवसर सुनिश्चित करने के लिए, उक्त साक्षियों से जिरह करने का एक सीमित अवसर प्रदान करना उचित समझा।

इस न्यायालय ने अपनी वैधता, औचित्य और क्षेत्राधिकार के दृष्टिकोण से आक्षेपित आदेश का परीक्षण किया है। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में विधि की कोई त्रुटि, तात्त्विक अनियमितता या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई दुर्बलता दिखाई नहीं देती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए विवेक को मनमाना या विधि के प्रावधानों के विपरीत नहीं कहा जा सकता है।

परिणामस्वरूप, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है।

तदनुसार, पुनरीक्षण **खारिज** किया जाता है। अभियुक्त राघवेंद्र उर्फ कल्लू को पी.डब्ल्यू.-1, संजय सिंह उर्फ शनी, और पी.डब्ल्यू.-2, सुमित कुमार से जिरह करने का अवसर प्रदान करने वाला विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश एतद्वारा पुष्ट किया जाता है।

20 अगस्त, 2026

प्रवेश मिश्रा

(न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”